

तालिबान का 'ऑपरेशन बदला': अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 19 चौकियों पर किया कब्जा, 55 सैनिक ढेर

अफगानिस्तान, 27 फरवरी। दक्षिण एशिया में दो पड़ोसी देशों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अब खुली जंग में तब्दील होता नजर आ रहा है। तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान द्वारा किए गए हालिया हवाई हमलों का करारा जवाब देते हुए सीमा पर स्थित 19 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों और एक मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। इस खुली संघर्ष में 55 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है।

अफगानिस्तान के वाइस स्पीकर हमदुल्लाह फिटरत के अनुसार यह कार्रवाई 22 फरवरी को पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगान सीमा के भीतर किए गए हमलों का बदला है जिसमें 19 अफगान नागरिकों की जान



चली गई थी।

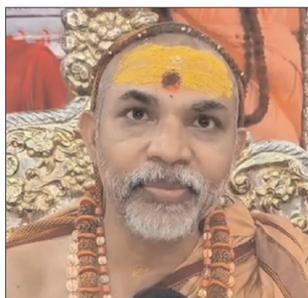
तालिबान ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए जवाबी सैन्य

अभियान शुरू किया है। तालिबान ने दावा किया है कि अफगान सेना (इस्लामिक अमीरात फोर्स) ने न

केवल चौकियों पर कब्जा किया बल्कि भारी मात्रा में गोला-बारूद भी अपने हाथ में लिया है।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक

इलाहाबाद, 27 फरवरी। एक अहम घटनाक्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उन्हें बड़ी राहत दी। कोर्ट के आदेश में मामले में अगली सुनवाई तक जबरदस्ती कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी गई है। राहत की मांग वाली याचिका चल रही कानूनी कार्रवाई के बीच दायर की गई थी, और बेंच ने अधिकारियों को शंकराचार्य के खिलाफ तुरंत कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुक्रवार को दोपहर करीब 3.45 बजे सत की एंटीसिपेटरी बेल अर्जी पर सुनवाई हो सकती है। उनके शिष्य संजय पांडे ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने रोजाना के धार्मिक काम जारी रखे और हमेशा की तरह अपनी रोज की पूजा-पाठ की। मठ में बड़ी



संख्या में मीडियाकर्मी मौजूद थे। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनके वकील कोर्ट में मौजूद थे और कोर्ट के सामने सारे सबूत पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। जिन्होंने झूठी कहानी बनाई है, वे बेनकाब हो रहे हैं। जैसे-जैसे लोगों को इस मनगढ़ंत मामले के बारे में पता चलेगा, सच्चाई सामने आ

जाएगी। मेडिकल जांच रिपोर्ट से जुड़े दावों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि एक मेडिकल रिपोर्ट हमारी सलिप्तता कैसे साबित कर सकती है? कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में गलत काम साबित हुआ है। यह किसी का बयान हो सकता है, लेकिन इतने दिनों बाद की गई मेडिकल रिपोर्ट का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत काम हुआ भी होता, तो इससे अपने आप यह साबित नहीं होता कि कौन जिम्मेदार था। उन्होंने कहा, रजो बच्चा कभी हमारे पास नहीं आया, उसे आसानी से हमारे नाम से नहीं जोड़ा जा सकता।

जलवायु परिवर्तन की मार अब महिलाओं के स्वास्थ्य पर, वाराणसी में होगा राष्ट्रीय मंथन

सुरेश गांधी वाराणसी। महिलाओं के स्वास्थ्य पर बढ़ते पर्यावरणीय बदलाव और जलवायु संकट के प्रभाव को लेकर वाराणसी में राष्ट्रीय स्तर का संवाद आयोजित किया जा रहा है। मेडवेज हेल्थ फाउंडेशन द्वारा 28 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से होटल ताज गंगेज में ह्यशी-शील्ड कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की रूपरेखा, उद्देश्य और विषय-वस्तु की विस्तृत जानकारी दी गई।

आयोजकों ने बताया कि यह कॉन्क्लेव महिलाओं के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चुनौतियों के संबंध पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मंच होगा। कार्यक्रम का मुख्य विषय ह्यपर्यावरणीय चुनौतियों के बीच महिलाओं के स्वास्थ्य का भविष्य रखा गया है, जिसमें स्वास्थ्य, सार्वजनिक नीति, सामाजिक

केजरीवाल शीशमहल में रहते हैं, विमानों में यात्रा करते हैं और ईमानदारी का ढोंग कर रहे : रेखा गुप्ता नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उनकी ईमानदारी के दावे को 'नाटक' करार दिया और कहा कि वह शीश महल में रहने और निजी विमानों में यात्रा करने के आदी हैं और फिर भी खुद को आम आदमी कहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आबकारी नीति में कुछ भी गलत नहीं था तो उसे वापस क्यों लिया गया। शहर की एक अदालत द्वारा आबकारी नीति मामले में आरोप मुक्त किए जाने के बाद, केजरीवाल ने दावा किया कि अदालत के फैसले से साबित होता है कि वह और आम आदमी पार्टी (आप) 'कट्टर ईमानदार' हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को खत्म करने और उनकी ईमानदारी और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए "फर्जी" मामले के माध्यम से एक साजिश रची गई थी।

बिहार के औरंगाबाद में एसयूवी की ट्रक से टक्कर में तीन लोगों की मौत, सात घायल

औरंगाबाद, 27 फरवरी। बिहार के औरंगाबाद जिले में दोपहर एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (NH-19) पर एक एसयूवी (स्व) और ट्रक के बीच हुई आमने-सामने की भीषण भिड़ंत में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

हादसा दोपहर में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर देव मोड़ के निकट हुआ। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एसयूवी में कुल 10 लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि वे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होकर झारखंड के धनबाद लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि मृतकों में से दो की पहचान तेज नारायण गुप्ता और विकास कुमार चौहान के रूप में हुई है, जबकि तीसरे व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो सकी है। औरंगाबाद मुफ्तसल



के थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया, शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि दुर्घटना के बाद सड़क पर कुछ देर के लिए

यातायात बाधित हुआ था, जिसे अब सामान्य कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रक चालक की तलाश जारी है। अशोक कुमार, थाना प्रभारी, औरंगाबाद मुफ्तसल शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और घायलों का सदर अस्पताल में बेहतरीन इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है।

कोलकाता में लगे भूकंप के झटके, लोग इमारतों से बाहर भागे

कोलकाता, 27 फरवरी। शुक्रवार को बांग्लादेश में आए 5.4 तीव्रता के भूकंप के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के आसपास के कई जिलों में तेज झटके महसूस किए गए। अचानक आए इन झटकों से लोगों में दहशत फैल गई और एहतियातन कई लोग दफ्तरों और इमारतों से बाहर निकल आए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, भूकंप का केंद्र ढाका के अगर्गांव स्थित इटकसिमिक सेंटर के दक्षिण-पश्चिम में था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 दर्ज की गई। कई लोगों के मोबाइल फोन पर आए भूकंप अलर्ट में तीव्रता करीब 5 बताई गई और केंद्र शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर दर्शाया गया।

कोलकाता के विभिन्न हिस्सों, खासकर ऑफिस कॉम्प्लेक्स और व्यावसायिक क्षेत्रों में मौजूद लोगों ने फनीचर के हिलने और इमारतों में कंपन महसूस होने की जानकारी



दी। कई कर्मशायल हब में कर्मचारियों ने स्थिति की गंभीरता

को लेकर अनिश्चितता के बीच तुरंत इमारतें खाली कर दीं और खुले स्थानों पर इकट्ठा हो गए।

फिलहाल किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।



DAKS REHAB CENTRE

(PARALYSIS PHYSIOTHERAPY CENTER AND OLD AGE HOME)

Contact us: 9820519851

विल्डिंग नंबर 3, प्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीवी नगर मुंबई-37

- * Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre
- * बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
- * वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
- * DM/HT/THYROID इन सब से कैसे बचें
- * NGO में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
- * चिकिस्ता उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
- * एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
- * पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
- * मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
- * विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
- * मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तियों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकिस्ता सुविधा उपलब्ध







NEW LIGHT CLASSES

TRADITION OF EXCELLENCE

2nd Floor, Sheetal Bldg. Near Diamond Talkies, L. T. Road, Borivali (West) Mumbai - 400 092 Maharashtra

ADMISSIONS OPEN

ALL OVER INDIA

ENROLL NOW



SMART CLASSROOM

(ONLINE/OFFLINE)

Courses Offered

- Std. XI & XII (Sci.)
- NEET
- JEE (Main & Advance)
- MHT-CET
- Polytechnic & Engg
- Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)

M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

राजस्थान के डिस्टर्ड एरिया बिल पर राजनीति



-संजय सक्सेना

राजस्थान की राजनीति इन दिनों एक ऐसे प्रस्तावित कानून के इर्द-गिर्द घूम रही है, जिसने सत्ता, विपक्ष, समाज और प्रशासन सभी को आमने-सामने ला खड़ा किया है। राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया डिस्टर्ड एरिया बिल 2026 सिर्फ एक विधायी पहल नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे सामाजिक ताने-बाने, संपत्ति के अधिकार और राज्य की कानून-व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि यह कानून

सांप्रदायिक तनाव, जबरन पलायन और जनसंख्या असंतुलन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए जरूरी है, जबकि विरोधियों को इसमें भय, दुरुपयोग और राजनीतिक मंशा की आशंका दिख रही है। राज्य में पिछले कुछ वर्षों से ऐसे इलाकों की चर्चा होती रही है, जहां सामुदायिक तनाव के बाद एक वर्ग के लोगों को अपने घर, दुकान या जमीन औने-पौने दामों पर बेचकर इलाका छोड़ना पड़ा। सरकार का कहना है कि दबाव, धमकी या सामाजिक असुरक्षा के माहौल में होने वाले ऐसे सौदे न सिर्फ पीड़ित परिवारों को कमजोर करते हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र में असंतुलन पैदा कर देते हैं। प्रस्तावित कानून इसी प्रक्रिया पर लगाम कसने की बात करता है। इसके तहत राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह किसी भी इलाके को सीमित अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर सके और वहां संपत्ति के लेन-देन को सख्त नियमों से बांध सके। सरकार का दावा यह बताई जा रही है कि अशांत घोषित इलाके में कोई भी अचल संपत्ति बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के खरीदी या बेची नहीं जा सकेगी। यह अनुमति तभी मिलेगी जब यह साबित हो कि सौदा पूरी सहमति से, बाजार मूल्य पर और बिना किसी दबाव के हो रहा है। साथ ही किरायेदारों को बेदखली से सुरक्षा देने की भी बात कही गई है। सरकार का तर्क है कि इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी, जो वर्षों से किसी इलाके में रहते आए हैं लेकिन अचानक बदले हालात के कारण खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। बिल में जिस अवधारणा पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है, वह है अनुचित जमावड़ा। कानून के मसौदे के अनुसार, यदि किसी क्षेत्र में किसी एक समुदाय का ऐसा संकेद्रण होता है, जो दबाव, मजबूरी या गलत मंशा के कारण हुआ हो और जिससे सामाजिक सौहार्द या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो, तो उस क्षेत्र को अशांत घोषित किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि यह प्रावधान भविष्य की आशंकाओं को देखते हुए रखा गया है, ताकि हालात बिगड़ने से पहले ही हस्तक्षेप किया जा सके।

राजस्थान की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार इसे एक एहतियाती कदम बता रही है। उसका तर्क है कि कई इलाकों में जनसंख्या के असंतुलन ने सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है और मौजूदा कानून ऐसे मामलों से निपटने में नाकामी साबित हुए हैं। कानून मंत्री जोगाराम पटेल पहले ही यह कह चुके हैं कि कुछ क्षेत्रों में हिंसा और दंगे की घटनाओं के बाद पुराने बाशिंदों के मजबूती में अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी। सरकार का मानना है कि यदि इस प्रवृत्ति को नहीं रोका गया, तो हालात और बिगड़ सकते हैं। विपक्षी केंद्रिय इस बिल को सत्ता का दुरुपयोग बताकर विरोध कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि यह कानून डर का माहौल पैदा करेगा और प्रशासन को मनमानी का हथियार दे देगा। उनका आरोप है कि सरकार विकास और रोजगार जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कानून ला रही है, जिससे समाज में अविश्वास बढ़ेगा। विपक्ष का यह भी कहना है कि किसी इलाके को अशांत घोषित करने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी और इसका इस्तेमाल राजनीतिक या सामुदायिक आधार पर किया जा सकता है।

राज्य सरकार इस आलोचना को खारिज करते हुए कहती है कि कानून में स्पष्ट समय-सीमा तय की गई है। किसी भी क्षेत्र को अधिकतम तीन साल या अधिसूचना में तय अवधि तक ही अशांत रखा जा सकेगा। इसके अलावा शिकायत मिलने पर एक विशेष जांच दल का गठन अनिवार्य होगा, जिसमें प्रशासन, पुलिस और स्थानीय निकाय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सरकार का दावा है कि इससे एकतरफा फैसलों की गुण्डाळी कम होगी। इस तरह के कानूनों का इतिहास देखा जाए तो यह प्रयोग नया नहीं है। देश में सबसे पहले 1983 में पंजाब में अशांत क्षेत्र से जुड़ा कानून बना था, जब वहां उपद्रव अपने चरम पर था। इसके बाद 1991 से गुजरात में भी ऐसे कानून लागू किया गया, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया। हाल के वर्षों में अक्सर सरकार ने भी अलग-अलग समुदायों के बीच जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। हालांकि 2016 में केंद्र सरकार ने यह कहते हुए पंजाब को इस श्रेणी से बाहर कर दिया था कि वहां हालात सामान्य हो चुके हैं। उस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिज्जु ने स्पष्ट किया था कि पंजाब अब अशांत क्षेत्र नहीं है और वहां सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम जैसी व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं रही।

राजस्थान के संदर्भ में सरकार कुछ खास इलाकों का उदाहरण देती है, जहां वर्षों से रहने वाले परिवारों के पलायन की बातें सामने आई हैं। जयपुर से कुछ दूरी पर स्थित कल्याणी मालपुरा और आसपास के इलाकों के किसी अक्सर चर्चा में रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक बदले सामाजिक समीकरणों के कारण डर का माहौल बना और कई परिवारों ने सुरक्षित भविष्य के लिए इलाका छोड़ना बेहतर समझा। सरकार इसी तरह की परिस्थितियों को रोकने के लिए कानून को जरूरी बता रही है। कानून के सख्त प्रावधान भी बहस का कारण हैं। यदि कोई व्यक्ति अशांत क्षेत्र में नियमों के खिलाफ संपत्ति का लेन-देन करता है, तो उसे तीन से पांच साल तक की जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती रखने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि बिना कड़ी सजा के ऐसे मामलों में रोक लगाना मुश्किल है, जबकि आलोचकों को डर है कि इससे आम नागरिकों को परेशान किया जा सकता है।

कानून का एक संवेदनशील पहलू यह भी है कि इसके दायरे में पुराने सौदे भी आ सकते हैं। यदि किसी संपत्ति का हस्तांतरण अमान्य घोषित होता है, तो विक्रेता को खरीदार को तय समय के भीतर पूरी रकम लौटानी होगी। समर्थकों का कहना है कि यह प्रावधान उन लोगों को न्याय देगा, जो दबाव में आकर अपनी संपत्ति बेचने को मजबूर हुए। विरोधियों को आशंका है कि इससे वर्षों पुराने विवाद फिर से खुल सकते हैं। राजस्थान में यह बहस अब सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रही। अलग-अलग, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रशासनिक विशेषज्ञ भी इसे अलग-वकील जरूरी ए से देख रहे हैं। कुछ का मानना है कि यदि समस्या गंभीर है और मौजूदा कानून नाकाम हो रहे हैं, तो सख्त कदम जरूरी हो सकते हैं। वहीं यह भी चेतावनी दी जा रही है कि किसी भी नए कानून का दुरुपयोग न हो, वरना उसका असर समाज में अविश्वास और उत्क्राव के रूप में सामने आ सकता है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह बिल कानून बनकर किस दिशा में जाता है और राजस्थान के सामाजिक परिदृश्य को किस तरह प्रभावित करता है।

पेंटागन ने ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के खतरे की चेतावनी दी

पेंटागन ईरान के खिलाफ लंबे मिलिट्री कैम्पेन को लेकर प्रैसिडेंट ट्रम्प के सामने चिंता जता रहा है। उसने सलाह दी है कि जिन वॉर प्लान पर विचार किया जा रहा है, उनमें अमरीका और सहयोगी देशों के नुकसान, कमजोर एयर डिफेंस और जरूरत से ज्यादा फायर होने जैसे रिस्क हैं। मौजूदा और पुराने अधिकारियों ने कहा कि ये



बोतलबंद पानी का भारत : सार्वजनिक जल प्रशासन की गहरी विफलता



- डॉ. सत्यवान सोरभ

भारत में बोतलबंद पानी पर बढ़ती निर्भरता केवल उपभोक्ता व्यवहार में आए बदलाव की कहानी नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक जल प्रशासन में व्याप्त गहरी और बहुस्तरीय प्रणालीगत समस्याओं की ओर भी स्पष्ट संकेत करती है। कभी जो नल का पानी नागरिकों के लिए बुनियादी अधिकार और राज्य की जिम्मेदारी माना जाता था, वही आज अविश्वास, असुरक्षा और असमानता का प्रतीक बनता जा रहा है। शहरों से लेकर कस्बों और यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में भी लोग पीने के लिए प्लास्टिक की बोतलों पर निर्भर होते जा रहे हैं। यह प्रवृत्ति न केवल आर्थिक बोझ बढ़ाती है, बल्कि प्यास, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

आधुनिक भारत में जल संकट को अक्सर वर्षा की कमी, जलवायु परिवर्तन या बढ़ती जनसंख्या से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि ये

सभी कारक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बोतलबंद पानी की लोकप्रियता का मूल कारण इनसे कहीं अधिक गहरा है। असल समस्या यह है कि नागरिकों का भरोसा सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणालियों से लगातार टूटता जा रहा है। नलों से आने वाले पानी की गुणवत्ता पर संदेह, नियमित आपूर्ति का अभाव, और पारदर्शिता की कमी ने लोगों को वैकल्पिक स्रोतों की ओर धकेल दिया है। राजस्थान अपनी बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में असफल होता है, तब बाजार उस खाली स्थान को भर देता है—अक्सर मुनाफे की शर्तों पर।

शहरी भारत में बोतलबंद पानी का उपयोग तेजी से बढ़ा है। महानगरों में तो यह लगभग जीवनशैली का हिस्सा बन चुका है। कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और यहां तक कि सरकारी दफ्तरों में भी बड़े जार और बोतलें आम दृश्य हैं। यह स्थिति विडम्बनापूर्ण है, क्योंकि इन्हीं शहरों में सबसे विकसित जल अवसंरचना होने का दावा किया जाता है। यदि इतनी सुविधाओं के बावजूद नागरिक सुरक्षित नल का पानी नहीं पी सकते, तो यह प्रशासनिक विफलता का सीधा प्रमाण है। पाइपलाइन की जर्जर हालत, सीवेज और पेयजल लाइनों का आपस में मिलना, तथा नियमित परीक्षण की कमी—ये सभी समस्याएं वर्षों से ज्ञात हैं, लेकिन समाधान आधे-अधूरे ही रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अलग होते हुए भी उतनी ही चिंताजनक है। वहां बोतलबंद पानी का उद्योग अपेक्षाकृत कम है, लेकिन जैसे-जैसे ग्रामीण बाजारों तक निजी कंपनियों की पहुंच बढ़ रही है, यह निर्भरता वहां भी बढ़ने लगी है। कई इलाकों में भूजल में फ्लोराइड, आर्सेनिक या आयनर की अधिकता के कारण लोग स्थानीय जल स्रोतों से उदरे लगे हैं। राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए सामुदायिक नल या हैंडपंप अक्सर या तो गंभीर खराब रहते हैं या फिर उनका पानी पीने योग्य नहीं होता। ऐसे में जिनके पास आर्थिक क्षमता है, वे बोतलबंद पानी खरीद लेते हैं, जबकि गरीब तबके दूषित पानी पीने को मजबूर रहते हैं। यह स्थिति जल के क्षेत्र में गहरी असमानता को जन्म देती है।

बोतलबंद पानी उद्योग का विस्तार अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। एक ओर यह उद्योग ह्यूमिडिटाइव और ह्यूमिडिटाइव का वादा करता है, वहीं दूसरी ओर इसके निर्यात में गंभीर खामियां हैं। कई बार यह पाया गया है कि बाजार में उपलब्ध बोतलबंद पानी भी गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता। इसके बावजूद उपभोक्ता इसे नल के चुनौती से अधिक सुरक्षित मानते हैं। यह धारणा स्वयं में सार्वजनिक जल संस्थानों की साख पर सवाल है। यदि राज्य द्वारा प्रमाणित और निर्यातित जल आपूर्ति प्रणाली पर नागरिक भरोसा नहीं करते, तो यह

लोकतांत्रिक शासन की विश्वसनीयता के लिए भी खतरे की घंटी है।

पर्यावरणीय दृष्टि से बोतलबंद पानी पर निर्भरता अत्यंत विनाशकारी है। प्लास्टिक की बोतलें कचरे के पहाड़ में बदल रही हैं। पुनर्चक्रण की दर बेहद कम है और अधिकांश प्लास्टिक अंततः नदियों, झीलों और समुद्रों में पहुंच जाता है। इसके अलावा, बोतलबंद पानी के उत्पादन में भी भारी मात्रा में जल और ऊर्जा की खपत होती है। यानी जिस संसाधन की कमी की बात की जा रही है, उसी का अत्यधिक दोहन करके एक कृत्रिम समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है। यह विरोधाभास नीति निमातों की अल्पकालिक सोच को उजागर करता है।

सार्वजनिक जल प्रशासन की समस्याएँ केवल तकनीकी नहीं हैं, वे संस्थागत और राजनीतिक भी हैं। जल प्रबंधन से जुड़े विभाग अक्सर संसाधनों की कमी, कुशल मानवबल के अभाव और आपसी समन्वय की समस्या से जूझते हैं। इसके अलावा, जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवा को राजनीतिक प्राथमिकता भी अक्सर नहीं मिलती। ग्रामीण घोषणाओं में बड़े बांध, नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं या स्मार्ट शहरों की बातें तो होती हैं, लेकिन रोजमर्रा की जल आपूर्ति को सुधारने पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। परिणामस्वरूप, छोटी-छोटी लेकिन महत्वपूर्ण

समस्याएँ वर्षों तक अनसुलझी रहती हैं।

निजीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति भी इस संकट को गहरा कर रही है। जब सार्वजनिक प्रणालियाँ कमजोर होती हैं, तो समाधान के रूप में निजी कंपनियों को आगे लाया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में इससे दक्षता बढ़ी है, लेकिन अक्सर इसका लाभ केवल उन लोगों को मिलता है जो भुगतान कर सकते हैं। पानी जैसे आवश्यक संसाधन का बाजार आधारित वितरण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। बोतलबंद पानी इस निजीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण है, जहां स्वच्छ पानी एक मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक उपभोक्ता वस्तु बन जाता है।

इस पूरी स्थिति का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि बोतलबंद पानी पर निर्भरता धीरे-धीरे सामान्य होती जा रही है। लोग इसे समस्या के लक्षण के बजाय समाधान के रूप में देखने लगे हैं। इससे सार्वजनिक दबाव कम होता है और प्रशासनिक सुधार की मांग कमजोर पड़ जाती है। जब नागरिक स्वयं वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते हैं, तो राज्य पर जवाबदेही का दबाव घट जाता है। यह चुपचाप स्वीकार की गई असफलता भविष्य में और बड़े संकटों को जन्म दे सकती है।

आवश्यकता इस बात की है कि जल को फिर से सार्वजनिक भलाई के रूप में स्थापित किया जाए। इसके लिए सबसे पहले नल के पानी की

गुणवत्ता और नियमितता सुनिश्चित करनी होगी। पारदर्शी जल परीक्षण, परिणामों की सार्वजनिक उपलब्धता और शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था नागरिकों का भरोसा बहाल कर सकती है। साथ ही, जल अवसंरचना में निवेश की प्राथमिकता देनी होगी—चाहे वह पाइपलाइन की मरम्मत हो, सीवेज प्रबंधन हो या जल शोधन संयंत्रों का आधुनिकीकरण।

इसके साथ-साथ जन जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। लोगों को यह समझना होगा कि बोतलबंद पानी दीर्घकालिक समाधान नहीं है। पर्यावरणीय और सामाजिक लागतों के बारे में जानकारी बढ़ाकर उपभोक्ता को बदला जा सकता है। स्कूलों, सामुदायिक संगठनों और स्थानीय निकायों की भूमिका इसमें अहम हो सकती है।

अंततः, बोतलबंद पानी बड़ती निर्भरता एक चेतावनी है। यह बताती है कि यदि सार्वजनिक जल प्रशासन को मजबूत नहीं किया गया, तो पानी जैसी बुनियादी आवश्यकता भी गहरी असमानता और संकट का कारण बन सकती है। यह समय है कि राज्य, समाज और नागरिक मिलकर इस प्रवृत्ति पर पुनर्विचार करें और पानी को फिर से भरोसे, समानता और सार्वजनिक जिम्मेदारी के दायरे में वापस लाएं। केवल तभी भारत अपनी बढ़ती प्यास को न्यायपूर्ण और टिकाऊ तरीके से बुझा सकेगा।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की चर्चा: सत्य का आईना या संस्था की गरिमा पर प्रहार?



-प्रियंका सोरभ

न्यायपालिका भारत के लोकतंत्र का संरक्षक स्तंभ है, जो संविधान की रक्षा करता है और नागरिकों को न्याय का आश्वासन देता है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा आठवीं की सोशल साइंस किताब पर सख्त रुख अपनाते हुए छाप, वितरण और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। किताब के 'हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका' अध्याय में 'न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार', लंबित मामलों की भारी संख्या, जजों की कमी और पूर्ण सौजेआई वी.आर. गवई के बयानों से उल्लेख था। सीजेआई सूर्यकांत ने इसे

न्यायपालिका को बदनाम करने की 'गहरी और सोची-समझी साजिश' करार दिया तथा शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। विवादित अध्याय के लेखकों की पहचान, उनकी योग्यता और सिलेबस फ्रेमिंग बैठकों की कार्यवाही प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। यह घटना न केवल शिक्षा नीति पर सवाल उठाती है, बल्कि संस्थागत गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार पर खुली चर्चा के बीच संतुलन की बहस को जन्म देती है। क्या स्कूली पाठ्यक्रम में ऐसी चर्चा गलत है? या यह समाज को सतर्क करने का माध्यम है?

भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(एक) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन अनुच्छेद 19(दो) में उचित प्रतिबंध भी हैं, जिनमें न्यायालय की अवमानना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का कदम अवमानना अधिनियम 1971 के दायरे में आता है, जहां न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री दंडनीय है।

कोर्ट ने तर्क दिया कि अध्याय चुनिंदीय (सेलेक्टिव) था—न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार का उल्लेख तो प्रमुख था, लेकिन विधायिका या कार्यपालिका पर ऐसा कोई जिक्र नहीं। लंबित मामलों को 'मैसिव बैकलॉग' कहना और जजों की कमी को चुनौती के रूप में पेश करना संस्था को कमजोर दिखाता है। पूर्व सीजेआई गवई के बयान का संदर्भ बिना पूर्ण संदर्भ के लिया गया, जो भ्रामक था। कोर्ट ने इसे 'डीप-रूटड कॉम्प्लेक्स' कहा, जो संकेत देता है कि यह केवल शैक्षणिक चूक नहीं, बल्कि सुनियोजित प्रयास हो सकता है। एनसीईआरटी द्वारा हाल में संशोधित पाठ्यक्रम में ऐसी सामग्री शामिल करना शिक्षा मंत्रालय की लापरवाही दर्शाता है। सिलेबस एक्सपर्ट कमिटी की बैठकों में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठे हैं—क्या लेखक राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित थे? कोर्ट ने गहन जांच का भरोसा दिलाया है, जो स्वातंत्र्य के लिए आवश्यक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार, भारत का

करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में 40/100 रहा, जो न्यायपालिका सहित संस्थाओं की चुनौतियों के रेखांकित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ब्रह्मचर्य हॉस्टल मामले या मेडिकल एडमिशन घोटालों में भ्रष्टाचार पर तीखी टिप्पणियां की हैं। जिस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था कि 'न्यूडिशियरी' में भ्रष्टाचार का एक मामला भी पूरी संस्था को दागदार बनाता है।' लेकिन स्कूलों किताब में इसे सामान्यीकृत कर पेश करना उचित नहीं। बच्चे 13-14 वर्ष के होते हैं—उन्हें तथ्यपरक ज्ञान दें, न कि पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण। अध्याय जवाबदेही, शक्तियों के पृथक्करण और सुधारों (जैसे फ्रास्ट-ट्रैक कोर्ट, जजों की भर्ती) पर केंद्रित होता तो उपयोगी होता। वर्तमान रूप में यह नकारात्मकता बोता है, जो युवा पीढ़ी में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास पैदा कर सकता है। हरियाणा जैसे राज्यों में, जहां पंचायती राज मजबूत है, स्थानीय न्याय व्यवस्था पहले से जूझ रही है—ऐसी सामग्री से ग्रामीण बच्चे हतोत्साहित होंगे। एनसीईआरटी की भूमिका पर

सवाल उठाना स्वाभाविक है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम सरलीकृत और भारतीयता-केंद्रित बनाने का लक्ष्य था, लेकिन यह विवाद उलटा असर डाल रहा है। मंत्रालय को सिलेबस फ्रेमिंग में बहुपक्षीय परामर्श अनिवार्य करना चाहिए—शिक्षाविद, न्यायिक विशेषज्ञ, अभिभावक संगठन शामिल हों। लेखकों की योग्यता जांचे-ब्यांवे राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं या सामान्य शिक्षक? कोर्ट ने डिजिटल कौशल्यां भी ज्वर करने को कहा, जो साइबर युग में चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यह कदम आवश्यक था, क्योंकि गलत सूचना वायरल हो सकती थी। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठों ने कोर्ट में इसे चुनिंदीय बताया, जो बहस को मजबूत करता है। अब जांच से यदि साजिश सिद्ध हुई, तो जिम्मेदारों पर राज्यों में, जहां पंचायती राज मजबूत है, स्थानीय न्याय व्यवस्था पहले से जूझ रही है—ऐसी सामग्री से ग्रामीण बच्चे हतोत्साहित होंगे। एनसीईआरटी की भूमिका पर

सवाल उठाना स्वाभाविक है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम सरलीकृत और भारतीयता-केंद्रित बनाने का लक्ष्य था, लेकिन यह विवाद उलटा असर डाल रहा है। मंत्रालय को सिलेबस फ्रेमिंग में बहुपक्षीय परामर्श अनिवार्य करना चाहिए—शिक्षाविद, न्यायिक विशेषज्ञ, अभिभावक संगठन शामिल हों। लेखकों की योग्यता जांचे-ब्यांवे राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं या सामान्य शिक्षक? कोर्ट ने डिजिटल कौशल्यां भी ज्वर करने को कहा, जो साइबर युग में चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यह कदम आवश्यक था, क्योंकि गलत सूचना वायरल हो सकती थी। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठों ने कोर्ट में इसे चुनिंदीय बताया, जो बहस को मजबूत करता है। अब जांच से यदि साजिश सिद्ध हुई, तो जिम्मेदारों पर राज्यों में, जहां पंचायती राज मजबूत है, स्थानीय न्याय व्यवस्था पहले से जूझ रही है—ऐसी सामग्री से ग्रामीण बच्चे हतोत्साहित होंगे। एनसीईआरटी की भूमिका पर

सवाल उठाना स्वाभाविक है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम सरलीकृत और भारतीयता-केंद्रित बनाने का लक्ष्य था, लेकिन यह विवाद उलटा असर डाल रहा है। मंत्रालय को सिलेबस फ्रेमिंग में बहुपक्षीय परामर्श अनिवार्य करना चाहिए—शिक्षाविद, न्यायिक विशेषज्ञ, अभिभावक संगठन शामिल हों। लेखकों की योग्यता जांचे-ब्यांवे राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं या सामान्य शिक्षक? कोर्ट ने डिजिटल कौशल्यां भी ज्वर करने को कहा, जो साइबर युग में चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यह कदम आवश्यक था, क्योंकि गलत सूचना वायरल हो सकती थी। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठों ने कोर्ट में इसे चुनिंदीय बताया, जो बहस को मजबूत करता है। अब जांच से यदि साजिश सिद्ध हुई, तो जिम्मेदारों पर राज्यों में, जहां पंचायती राज मजबूत है, स्थानीय न्याय व्यवस्था पहले से जूझ रही है—ऐसी सामग्री से ग्रामीण बच्चे हतोत्साहित होंगे। एनसीईआरटी की भूमिका पर

सवाल उठाना स्वाभाविक है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम सरलीकृत और भारतीयता-केंद्रित बनाने का लक्ष्य था, लेकिन यह विवाद उलटा असर डाल रहा है। मंत्रालय को सिलेबस फ्रेमिंग में बहुपक्षीय परामर्श अनिवार्य करना चाहिए—शिक्षाविद, न्यायिक विशेषज्ञ, अभिभावक संगठन शामिल हों। लेखकों की योग्यता जांचे-ब्यांवे राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं या सामान्य शिक्षक? कोर्ट ने डिजिटल कौशल्यां भी ज्वर करने को कहा, जो साइबर युग में चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यह कदम आवश्यक था, क्योंकि गलत सूचना वायरल हो सकती थी। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठों ने कोर्ट में इसे चुनिंदीय बताया, जो बहस को मजबूत करता है। अब जांच से यदि साजिश सिद्ध हुई, तो जिम्मेदारों पर राज्यों में, जहां पंचायती राज मजबूत है, स्थानीय न्याय व्यवस्था पहले से जूझ रही है—ऐसी सामग्री से ग्रामीण बच्चे हतोत्साहित होंगे। एनसीईआरटी की भूमिका पर

सवाल उठाना स्वाभाविक है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम सरलीकृत और भारतीयता-केंद्रित बनाने का लक्ष्य था, लेकिन यह विवाद उलटा असर डाल रहा है। मंत्रालय को सिलेबस फ्रेमिंग में बहुपक्षीय परामर्श अनिवार्य करना चाहिए—शिक्षाविद, न्यायिक विशेषज्ञ, अभिभावक संगठन शामिल हों। लेखकों की योग्यता जांचे-ब्यांवे राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं या सामान्य शिक्षक? कोर्ट ने डिजिटल कौशल्यां भी ज्वर करने को कहा, जो साइबर युग में चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यह कदम आवश्यक था, क्योंकि गलत सूचना वायरल हो सकती थी। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठों ने कोर्ट में इसे चुनिंदीय बताया, जो बहस को मजबूत करता है। अब जांच से यदि साजिश सिद्ध हुई, तो जिम्मेदारों पर राज्यों में, जहां पंचायती राज मजबूत है, स्थानीय न्याय व्यवस्था पहले से जूझ रही है—ऐसी सामग्री से ग्रामीण बच्चे हतोत्साहित होंगे। एनसीईआरटी की भूमिका पर

सवाल उठाना स्वाभाविक है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम सरलीकृत और भारतीयता-केंद्रित बनाने का लक्ष्य था, लेकिन यह विवाद उलटा असर डाल रहा है। मंत्रालय को सिलेबस फ्रेमिंग में बहुपक्षीय परामर्श अनिवार्य करना चाहिए—शिक्षाविद, न्यायिक विशेषज्ञ, अभिभावक संगठन शामिल हों। लेखकों की योग्यता जांचे-ब्यांवे राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं या सामान्य शिक्षक? कोर्ट ने डिजिटल कौशल्यां भी ज्वर करने को कहा, जो साइबर युग में चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यह कदम आवश्यक था, क्योंकि गलत सूचना वायरल हो सकती थी। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठों ने कोर्ट में इसे चुनिंदीय बताया, जो बहस को मजबूत करता है। अब जांच से यदि साजिश सिद्ध हुई, तो जिम्मेदारों पर राज्यों में, जहां पंचायती राज मजबूत है, स्थानीय न्याय व्यवस्था पहले से जूझ रही है—ऐसी सामग्री से ग्रामीण बच्चे हतोत्साहित होंगे। एनसीईआरटी की भूमिका पर

सवाल उठाना स्वाभाविक है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम सरलीकृत और भारतीयता-केंद्रित बनाने का लक्ष्य था, लेकिन यह विवाद उलटा असर डाल रहा है। मंत्रालय को सिलेबस फ्रेमिंग में बहुपक्षीय परामर्श अनिवार्य करना चाहिए—शिक्षाविद, न्यायिक विशेषज्ञ, अभिभावक संगठन शामिल हों। लेखकों की योग्यता जांचे-ब्यांवे राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं या सामान्य शिक्षक? कोर्ट ने डिजिटल कौशल्यां भी ज्वर करने को कहा, जो साइबर युग में चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यह कदम आवश्यक था, क्योंकि गलत सूचना वायरल हो सकती थी। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठों ने कोर्ट में इसे चुनिंदीय बताया, जो बहस को मजबूत करता है। अब जांच से यदि साजिश सिद्ध हुई, तो जिम्मेदारों पर राज्यों में, जहां पंचायती राज मजबूत है, स्थानीय न्याय व्यवस्था पहले से जूझ रही है—ऐसी सामग्री से ग्रामीण बच्चे हतोत्साहित होंगे। एनसीईआरटी की भूमिका पर

सवाल उठाना स्वाभाविक है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम सरलीकृत और भारतीयता-केंद्रित बनाने का लक्ष्य था, लेकिन यह विवाद उलटा असर डाल रहा है। मंत्रालय को सिलेबस फ्रेमिंग में बहुपक्षीय परामर्श अनिवार्य करना चाहिए—शिक्षाविद, न्यायिक विशेषज्ञ, अभिभावक संगठन शामिल हों। लेखकों की योग्यता जांचे-ब्यांवे राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं या सामान्य शिक्षक? कोर्ट ने डिजिटल कौशल्यां भी ज्वर करने को कहा, जो साइबर युग में चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यह कदम आवश्यक था, क्योंकि गलत सूचना वायरल हो सकती थी। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठों ने कोर्ट में इसे चुनिंदीय बताया, जो बहस को मजबूत करता है। अब जांच से यदि साजिश सिद्ध हुई, तो जिम्मेदारों पर राज्यों में, जहां पंचायती राज मजबूत है, स्थानीय न्याय व्यवस्था पहले से जूझ रही है—ऐसी सामग्री से ग्रामीण बच्चे हतोत्साहित होंगे। एनसीईआरटी की भूमिका पर

सवाल उठाना स्वाभाविक है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम सरलीकृत और भारतीयता-केंद्रित बनाने का लक्ष्य था, लेकिन यह विवाद उलटा असर डाल रहा है। मंत्रालय को सिलेबस फ्रेमिंग में बहुपक्षीय परामर्श अनिवार्य करना चाहिए—शिक्षाविद, न्यायिक विशेषज्ञ, अभिभावक संगठन शामिल हों। लेखकों की योग्यता जांचे-ब्यांवे राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं या सामान्य शिक्षक? कोर्ट ने डिजिटल कौशल्यां भी ज्वर करने को कहा, जो साइबर युग में चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यह कदम आवश्यक था, क्योंकि गलत सूचना वायरल हो सकती थी। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठों ने कोर्ट में इसे चुनिंदीय बताया, जो बहस को मजबूत करता है। अब जांच से यदि साजिश सिद्ध हुई, तो जिम्मेदारों पर राज्यों में, जहां पंचायती राज मजबूत है, स्थानीय न्याय व्यवस्था पहले से जूझ रही है—ऐसी सामग्री से ग्रामीण बच्चे हतोत्साहित होंगे। एनसीईआरटी की भूमिका पर

सवाल उठाना स्वाभाविक है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम सरलीकृत और भारतीयता-केंद्रित बनाने का लक्ष्य था, लेकिन यह विवाद उलटा असर डाल रहा है। मंत्रालय को सिलेबस फ्रेमिंग में बहुपक्षीय परामर्श अनिवार्य करना चाहिए—शिक्षाविद, न्यायिक विशेषज्ञ, अभिभावक संगठन शामिल हों। लेखकों की योग्यता जांचे-ब्यांवे राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं या सामान्य शिक्षक? कोर्ट ने डिजिटल कौशल्यां भी ज्वर करने को कहा, जो साइबर युग में चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यह कदम आवश्यक था, क्योंकि गलत सूचना वायरल हो सकती थी। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठों ने कोर्ट में इसे चुनिंदीय बताया, जो बहस को मजबूत करता है। अब जांच से यदि साजिश सिद्ध हुई, तो जिम्मेदारों पर राज्यों में, जहां पंचायती राज मजबूत है, स्थानीय न्याय व्यवस्था पहले से जूझ रही है—ऐसी सामग्री से ग्रामीण बच्चे हतोत्साहित होंगे। एनसीईआरटी की भूमिका पर

सवाल उठाना स्वाभाविक है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम सरलीकृत और भारतीयता-केंद्रित बनाने का लक्ष्य था, लेकिन यह विवाद उलटा असर डाल रहा है। मंत्रालय को सिलेबस फ्रेमिंग में बहुपक्षीय परामर्श अनिवार्य करना चाहिए—शिक्षाविद, न्यायिक विशेषज्ञ, अभिभावक संगठन शामिल हों। लेखकों की योग्यता जांचे-ब्यांवे राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं या सामान्य शिक्षक? कोर्ट ने डिजिटल कौशल्यां भी ज्वर करने को कहा, जो साइबर युग में चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यह कदम आवश्यक था, क्योंकि गलत सूचना वायरल हो सकती थी। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठों ने कोर्ट में इसे चुनिंदीय बताया, जो बहस को मजबूत करता है। अब जांच से यदि साजिश सिद्ध हुई, तो जिम्मेदारों पर राज्यों में, जहां पंचायती राज मजबूत है, स्थानीय न्याय व्यवस्था पहले से जूझ रही है—ऐसी सामग्री से ग्रामीण बच्चे हतोत्साहित होंगे। एनसीईआरटी की भूमिका पर

सवाल उठाना स्वाभाविक है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम सरलीकृत और भारतीयता-केंद्रित बनाने का लक्ष्य था, लेकिन यह विवाद उलटा असर डाल रहा है। मंत्रालय को सिलेबस फ्रेमिंग में बहुपक्षीय परामर्श अनिवार्य करना चाहिए—शिक्षाविद, न्यायिक विशेषज्ञ, अभिभावक संगठन शामिल हों। लेखकों की योग्यता जांचे-ब्यांवे राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं या सामान्य शिक्षक? कोर्ट ने डिजिटल कौशल्यां भी ज्वर करने को कहा, जो साइबर युग में चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यह कदम आवश्यक था, क्योंकि गलत सूचना वायरल हो सकती थी। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठों ने कोर्ट में इसे चुनिंदीय बताया, जो बहस को मजबूत करता है। अब जांच से यदि साजिश सिद्ध हुई, तो जिम्मेदारों पर राज्यों में, जहां पंचायती राज मजबूत है, स्थानीय न्याय व्यवस्था पहले से जूझ रही है—ऐसी सामग्री से ग्रामीण बच्चे हतोत्साहित होंगे। एनसीईआरटी

समता विद्या मंदिर स्कूल में ग्रंथ दिंडी समारोह उत्साह के साथ संपन्न



मुंबई (उत्तरशक्ति)। मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा के उद्देश से गुंजते वातावरण में मराठी भाषा गौरव दिवस के अवसर पर साकीनाका स्थित समता विद्या मंदिर स्कूल में ग्रंथ दिंडी समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने संतो द्वारा रचित विभिन्न ग्रंथों की दिंडी विद्यालय परिसर में निकाली। छत्र-छात्राओं ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर तथा नामजप करते हुए दिंडी में भाग लिया। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि ने अनेक संतों और वीरों को जन्म दिया है। विद्यार्थियों ने उन्हीं संतों और वीरों की वेशभूषा धारण कर उनकी सजीव झलक प्रस्तुत की, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। सुबह 7 बजे दिंडी का शुभारंभ हुआ। कक्षा पाँचवीं से नवमी तक के विद्यार्थियों ने इस उपक्रम में उत्साहपूर्वक सहभाग दर्ज किया। पूरे विद्यालय परिसर में भक्ति और संस्कृति का वातावरण निर्मित हो गया था। विद्यालय के सचिव राजेश सुभेदार तथा कार्याध्यक्ष ज्योति सुभेदार के मार्गदर्शन में यह मराठी भाषा गौरव उत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विद्यार्थियों में मराठी भाषा, साहित्य और संस्कृति के प्रति अभिमान जागृत करना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था, ऐसा विद्यालय के सचिव राजेश सुभेदार ने बताया। इस समारोह को सफल बनाने के लिए सांस्कृतिक प्रमुख भरत भोई, वैशाली हांडे, प्रतीक्षा गोरे, नीलम डीमेलो सहित अन्य शिक्षकों ने विशेष परिश्रम किया।

रोटरी क्लब द्वारा भिंडी में विशाल नेत्र जांच शिविर के आयोजन में 30 निःशुल्क मोतियाबिंद के मरीज चिन्हित



आचार्य सुरजपाल यादव/भिंडी (उत्तरशक्ति)। भिंडी के अखिल पद्मशाली समाज हाल पद्मानगर स्थित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब ऑफ भिंडी सेंट्रल एवं रोटरी क्लब ऑफ अंबरनाथ नॉर्थ के संयुक्त तत्वावधान में एक विशाल निःशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस सेवा अभियान में अखिल पद्मशाली समाज, सावला कंसल्टेंसी (बिपिन सावला), वीवीएम ग्रुप एवं परिवार का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। शिविर के दौरान चिन्हित जरूरतमंद मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन भक्ति वेदांत हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में सीएसआर फंड के माध्यम से पूर्णतः निःशुल्क किए जाएंगे। इस अवसर पर रोटरी क्लब की ओर से हॉस्पिटल प्रबंधन एवं चिकित्सा टीम का विशेष सम्मान कर आभार व्यक्त किया गया। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा कुल 130 नागरिकों की सूक्ष्म नेत्र जांच की गई, वहीं 30 जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क चर्म विरहित किए गये और 30 लोगों में मोतियाबिंद चिन्हित किया गया जिनका ऑपरेशन भक्ति वेदांत हॉस्पिटल मीरारोड में 5 मार्च को भिंडी से बस द्वारा ले जाया जायेगा और 6 मार्च को ऑपरेशन किया जायेगा, 7 मार्च को वापस भिंडी लाया जायेगा। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का सफल संचालन प्रोजेक्ट चेरर पास्ट प्रेसिडेंट संतोष जी एवं पास्ट प्रेसिडेंट अजय नायक वशिष्ठ जी के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में रोटरी क्लब ऑफ भिंडी सेंट्रल के सदस्य अरविंद भोईर, सतीशा भोजने, महेश खडके, नीता भोईर, पवन सिंघल, बिपिन सावला एवं प्रह्लाद तलेले ने सक्रिय भूमिका निभाई। साथ ही अखिल पद्मशाली समाज के अध्यक्ष रामकृष्ण पोद्दारबत्तीनी, सचिव राजू मांजोरी, कोंका मलेशम, बलराम अवधूत सहित समाज के सभी सदस्यों ने कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष किशोर वेगल एवं सचिव सुदर्शन जी ने सभी दानदाताओं, रोटरी सदस्यों तथा विशेष रूप से सावला कंसल्टेंसी के बिपिन सावला और अखिल पद्मशाली समाज के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।

बोईसर के ओमसाईनगर में गंदा पानी सड़क पर, नागरिकों में रोष

पालघर (उत्तरशक्ति)। पालघर जिले के बोईसर ग्रामपंचायत क्षेत्र अंतर्गत ओमसाईनगर परिसर में गंदा पानी सड़क पर छोड़े जाने से गंभीर स्वच्छता व स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो गई है। स्थानीय रहिवासियों ने इस संबंध में ग्रामपंचायत कार्यालय बोईसर, ता. जि. पालघर को लिखित शिकायत देकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

रहिवासियों के अनुसार कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर अपने नाले का गंदा पानी बिना किसी उचित व्यवस्था के सीधे सड़क पर छोड़ा जा रहा है। इसके कारण पूरे परिसर में दुर्गंध फैल रही है तथा सड़क पर गंदा पानी जमा होने से आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है। विशेष रूप से स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि संबंधित लोगों को कई बार समझाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया है। बरसात या पानी की अधिकता के समय स्थिति और भी विकट हो जाती है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका है। निवासियों ने ग्रामपंचायत प्रशासन से मांग की है कि स्थल निरीक्षण कर तत्काल उचित कार्रवाई की जाये तथा जिम्मेदार लोगों पर आवश्यक दंडात्मक कदम उठाया जाये, ताकि परिसर में स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्था बनी रहे। अब देखना यह होगा कि ग्रामपंचायत प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कितनी शीघ्रता से संज्ञान लेकर समाधान करता है।

पेसा क्षेत्र में 819 शिक्षण सेवकों की हुई नियुक्ति

पालघर (उत्तरशक्ति)। पेसा क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षण सेवकों पर रिक्त 819 पदों की भर्ती प्रक्रिया को कानूनी व पारदर्शी तरीके से पूर्ण कर संबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश प्रदान किये गये हैं। यह जानकारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे ने दी।

इस निर्णय से पेसा क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ही स्थानीय अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों को न्याय मिला है। पेसा क्षेत्र की भर्ती को लेकर वर्ष 2023 में मामला सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुआ था। इसके बाद 5 अक्टूबर 2024 के सामान्य प्रशासन विभाग के शासन निर्णय

द बाँडी शॉप के साथ होली पर पाएं सुरक्षित, स्वस्थ और दमकती त्वचा

मुंबई। होली के रंगों और बदलते मौसम के बीच त्वचा और बालों की देखभाल पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। सर्दियों से गर्मी की ओर बढ़ते इस मौसम में तैज धूप, धूल और रंग त्वचा की नमी छीन सकते हैं। ऐसे में द बाँडी शॉप होली से पहले और बाद की संपूर्ण स्किन और हेयर केयर रूटीन के साथ उपभोक्ताओं को सुरक्षित और बेहतर उत्सव मनाने के लिए प्रेरित करता है। होली से पहले त्वचा को तैयार करना बेहद जरूरी है। द बाँडी शॉप का टी ट्री स्किन क्लियरिंग फेशियल वॉश त्वचा की गहराई से सफाई कर अतिरिक्त तेल और अशुद्धियों को हटाता है। इसके बाद विटामिन ई हाइड्रेटिंग टोनर त्वचा को नमी बनाए रखने और उसे ठंडक देने में मदद करता है। विटामिन ई बैरियर क्रीम क्रीम मॉइस्चर बैरियर को मजबूत कर लंबे समय तक

के अनुसार संबंधित अभ्यर्थियों को मानधन आधार पर कार्यरत रखा गया था। आगे 11 फरवरी 2026 के शासन निर्णय तथा 25 फरवरी 2026 को आयुक्त (शिक्षण) के पत्र के अनुसार इन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति रूप से शिक्षण सेवक पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।

भर्ती प्रक्रिया में कुल 819 रिक्त पदों को निर्धारित सीमा के भीतर भरा गया। पेसा क्षेत्र में ग्रामवार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात के अनुसार पदों का वितरण किया गया। जिन गांवों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% तक है, वहां 25% पद भरे गये। 25% से 50% जनसंख्या वाले गांवों में 50% पद भरे गये। 50% से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में रिक्त पदों

हाइड्रेशन प्रदान करती है, जबकि स्किन डिफेंस मल्टी-प्रोटेक्शन लाइट एसेंस SPF 50 PA+++ हल्के, नॉन-ग्रीसी फॉर्मूल के साथ प्रभावी सन प्रोटेक्शन देता है। होली खेलने के बाद त्वचा और बालों को पोषण और मरम्मत की आवश्यकता होती है। बनाना टूली नरिशिंग शैम्पू रूखे और बेजान बालों को मुलायम बनाता है, वहीं शिया इट्स रिपेयर हेयर मास्क बालों को अंदर से मजबूती देता है। शरीर की कोमल सफाई के लिए ड्यूबेरी बाथ एंड शॉवर जेल रंगों को हटाकर ताजगी प्रदान करता है। अंत में, शिया बाँडी बटर त्वचा को गहराई से पोषण देकर लंबे समय तक हाइड्रेटेड और मुलायम बनाए रखता है। द बाँडी शॉप का मानना है कि सही तैयारी और बाद की देखभाल के साथ होली का उत्सव पूरी तरह सुरक्षित और आनंदमय बन सकता है।

यादव जी की लव स्टोरी के विरोध में निकाला मोर्चा

नवीं मुंबई (उत्तरशक्ति)। पनवेल में यादव समाज द्वारा फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के विरोध में एक मोर्चा निकाला गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फिल्म की विषय-वस्तु समाज की भावनाओं को आहत करती है, इसलिए फिल्म के शीर्षक और आपतिजनक अंशों में बदलाव किया जाए तथा निमाताओं को समाज विरोधी मानसिकता से बचने की चेतावनी दी जाए।

यह मोर्चा यादव समाज की संस्था विषय यादव समाज के बैनर तले आयोजित किया गया। संस्था के अध्यक्ष मोतीलाल यादव, वरिष्ठ सलाहकार आर.एन. यादव, डी.एन. यादव और जितेंद्र यादव सहित समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उन्होंने समाज के लोगों से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि यदि



फिल्म में आवश्यक संशोधन नहीं किया गया, तो अगला कदम उठाते हुए मुंबई स्थित केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (उद्धर) के मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

प्रदर्शन के दौरान पनवेल के तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें फिल्म की समीक्षा कर आवश्यक बदलाव करने की मांग की गई। मोर्चे को सफल बनाने में सुरेश

बोईसर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित, सैकड़ों लोगों ने उटाय लाम

पालघर (उत्तरशक्ति/अजीत सिंह)। श्री साई श्रद्धा को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, बोईसर के तत्वावधान में मुख्यमंत्री सहायता निधि व धर्मदाय गुणगान्य मदत कक्ष, पालघर के सहयोग से शुक्रवार 27 फरवरी 2026 को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर साई श्रद्धा पतसंस्थामार्फत जिला परिषद स्कूल, दांडीपाड़ा में आयोजित हुआ।

शिविर में मेट्रो फिनिस मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, बोईसर के अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने उपस्थित नागरिकों की स्वास्थ्य जांच की। शिविर के अंतर्गत रक्तचाप (बीपी), मधुमेह (शुगर) जांच, वीएमआई, ईसीजी, मशीन द्वारा नेत्र



जांच तथा निःशुल्क रक्त जांच जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। साथ ही डॉक्टरों द्वारा आवश्यकतानुसार परामर्श और मार्गदर्शन भी दिया गया। पूर्व जिला परिषद सदस्या व श्री साई श्रद्धा को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, बोईसर की अध्यक्ष रंजना सेंडे ने बताया कि ग्रामीण एवं निम्न आय वर्ग के गरीब व जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण

शासन व सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हुआ पालन : मनोज रानडे



के 50% पद भरे गये। इसके अतिरिक्त मानधन पर कार्यरत 16 ग्रामसेवकों को भी नियुक्ति आदेश

सोनोपन्त दांडेकर महाविद्यालय में मना मराठी राजभाषा गौरव दिन

पालघर (उत्तरशक्ति)। सोनोपन्त दांडेकर शिक्षण मंडली, पालघर द्वारा संचालित सोनोपन्त दांडेकर कला, वि.स.आपटे वाणिज्य व म.ह. मेहता विज्ञान महाविद्यालय के मराठी वाङ्मय मंडल की ओर से मराठी राजभाषा गौरव दिवस बड़े उत्साह और गरिमाय वातावरण में मनाया गया। महान कवि वि. वा. शिरवाडकर (कुसुमाग्रज) की जयंती के अवसर पर मनमुद्राद शीर्षक से कविता, गीत व संवाचों से सजे विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में टीम मनमुद्राद ने मराठी साहित्य की समृद्ध परंपरा और उसकी सौंदर्य दृष्टि को विद्यार्थियों के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। ओवी, भजन, भक्तिगीत व भावगीत जैसी विविध विधाओं की रचनाओं का समीर पवार, अस्मिता जाधव व भाग्यश्री गोखले ने मधुर स्वर में गायन कर श्रोताओं को



मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्हें साहिल म्हस्कर ने वादन के माध्यम से सशक्त संगत दी। शैलेश पाटील ने कविताओं का प्रभावी पाठ करते हुए संस्मरण और रोचक प्रसंग साझा किये जिससे पूरे कार्यक्रम को एक सुसंगत व भावपूर्ण स्वरूप मिला।

इस अवसर पर लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे की ' माझी मैना गावला राहिली तथा प्रख्यात कवि

नामदेव ढसाल की माणसाने कविता के माध्यम से साहित्य में निहित सामाजिक और राजनीतिक चेतना को रेखांकित किया गया। साथ ही ना.धो. महानोर एवं मंगेश पाडगावकर की प्रेम कविताओं को भी विद्यार्थियों ने उत्स्फूर्त सराहना दी। मराठी विभाग की छात्राएं कांचन धुयाल, संस्कृती राहे और मयुरी भोईर ने मल्लार कोली बोली में

प्रदान कर पेसा क्षेत्र में उनकी सविदा आधार पर नियमित नियुक्ति की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे ने स्पष्ट किया कि सभी 819 अभ्यर्थियों को रिक्त पदों की 50% सीमा के भीतर समायोजित किया गया है तथा शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए आदेश जारी किये गये हैं। नियुक्ति आदेश प्राप्त करने के बाद सभी अभ्यर्थियों ने खुशी व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन के प्रति आभार प्रकट किया। नियुक्ति आदेश वितरण कार्यक्रम में सांसद डॉ. हेमंत सवरा, विधायक राजेंद्र गावित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक पाटील तथा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सोनाली मातेकर उपस्थित थे।

मीरा भायंदर मनापा द्वारा स्वच्छ सुंदर और स्वस्थ रखने की साप्ताहिक विशेष पहल स्वच्छता अभियान का शुभारंभ

तारकेश्वर पांडे मीरा भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा भायंदर में महापौर श्रीमती डिंपल विनोद मेहता, एवं नगर आयुक्त राधा विनोद शर्मा, ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया है। मीरा भायंदर नगरनिगम द्वारा सामूहिक गहन सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मीरा भायंदर शहर की स्वच्छता व्यवस्था को अधिक कुशल, प्रभावी और सतत बनाना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के मद्देनजर शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण पहल की गई है, और नगर प्रशासन नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छता की शपथ लेकर अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महापौर द्वारा शहर के सैलून एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को प्रयुक्त ब्लेड कचरे के लिए ब्लेड विन वितरित किया गया। साथ ही, विसलेरी के माध्यम से प्लास्टिक की बोतलों से बने 70 टिकाऊ विन का अनायोजन किया गया। शहर के दो चयनित क्षेत्रों में हर शुक्रवार को योजनाबद्ध तरीके से व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के हालिया चरण में, वाई समिति संख्या 3 के अंतर्गत कुल 10 स्थानों पर व्यापक स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। इस अवसर पर पार्षद कुसुम गुप्ता, सिता पाटिल, मदन सिंह, रजनीकांत माथकर, शाहानु संहल, जया दत्ता, दिव्या परव, मुन्ना सिंह,



सचिन डोंगरे, आकांक्षा विकरं, सहायक आयुक्त योगेश गुणिजन, सहायक आयुक्त दत्तात्रेय वकुटे, स्वच्छता निरीक्षक और कर्मचारी उपस्थित थे।

यह अभियान विशेष रूप से सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, नालियों, बाजारों, कचरा संग्रहण केंद्रों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और स्वच्छता के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को लक्षित कर रहा है। आधुनिक यांत्रिक उपकरणों का उपयोग गहन सफाई के लिए किया जा रहा है और जेटिंग मशीन, सक्शन मशीन, सड़क सफाई मशीन आदि उपकरणों की सहायता से सफाई कार्य अधिक कुशलता से किया जा रहा है। अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विशेष उपाय लागू किए जा रहे हैं।

सार्वजनिक स्थानों पर धूपदान से होने वाले धागों की पहचान कर-के, उन स्थानों को रेड स्पॉट्स अभियान के माध्यम से पूरी तरह से साफ किया जा रहा है और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। खुले में शौच या गंदगी पाए जाने वाले स्थानों पर

वेलो स्पॉट अभियान चलाकर निवारक उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से लगाए गए पोस्टर, बैनर और स्टिकर हटाकर शहर को सुंदर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पचास वर्ष संरक्षण के लिए, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों और व्यवसायों पर जुमाना लगाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर कुड़ा फेंकने, खुले या गंदगी फैलाने वाले कचरे के थिंकाने करवाई करने और स्वच्छता के प्रति अनुशासन स्थापित करने के लिए विशेष टीमों गठित की जा रही हैं। सखोल स्वच्छता अभियान नियमित रूप से चलाया जाएगा और नगर प्रशासन नागरिकों से शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाए रखने के लिए इस स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील करता है। मीरा भायंदर नगर निगम स्वच्छता के क्षेत्र में एक बार फिर उल्लेखनीय स्थान प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण कदम है।

मीरा भायंदर नगर निगम में मराठी भाषा गौरव दिवस धूमधाम से मनाया गया

मीरा भायंदर (उत्तरशक्ति)। कल 27 फरवरी, 2026 को मीरा भायंदर नगर निगम द्वारा मराठी भाषा गौरव दिवस को बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में शहर के महापौर श्रीमती डिंपल विनोद मेहता, उप महापौर ध्रुवकिशोर मनसारांम पाटिल, आयुक्त राधा विनोद ए. शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे, उपायुक्त डॉ.सचिन बंगर तथा प्रणाली घोंगे उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम मुख्यालय से डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर भवन तक स्कूली छात्रों के साथ भव्य जुलूस निकाला गया। जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और मराठी भाषा के संरक्षण का संदेश देने वाले पोस्टर पकड़े हुए थे। इस जुलूस ने क्षेत्र में मराठी भाषा गौरव दिवस का उत्साहपूर्ण वातावरण बना दिया। इसके बाद महापौर, उप महापौर और आयुक्त ने कवि कुसुमाग्रज और सरस्वती माता की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों ने मराठी भाषा की समृद्ध परंपरा का गुणगान किया और इसके संरक्षण एवं संवर्धन का आवश्यकता पर बल दिया। अपने भाषण में महापौर श्रीमती डिंपल मेहता ने कहा कि समय के साथ अग्रणी भाषा का महत्व निश्चित रूप से बढ़ रहा है; फिर भी,



मराठी हमारी मातृभाषा है और इसे सर्वोच्च स्थान देना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने सभी से मराठी भाषा के संरक्षण, प्रचार-प्रसार और दैनिक जीवन में इसके अधिक से अधिक उपयोग की अपील की। लेखिका प्रज्ञा पंडित और प्रोफेसर डॉ. संतोष राणे कार्यक्रम में सम्मानित वक्ताओं के रूप में उपस्थित थीं। उन्होंने मराठी भाषा के इतिहास, इसकी शास्त्रीय परंपरा और आधुनिक समय में इसकी उपयोगिता पर प्रभावी मार्गदर्शन देकर उपस्थित लोगों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में शहर के पार्षदों, अधिकारियों और कर्मचारियों, शिक्षकों तथा छात्रों की बड़ी संख्या ने उपस्थिति रही। मराठी भाषा के गौरव और इसके प्रचार-प्रसार की भावना को मजबूत करने वाला यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

उत्तरशक्ति

* संपादक: ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादक: प्रेम चंद मिश्रा
* प्रबंध संपादक: डा. शेषधर बिन्दु
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालय:
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्ल्यू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जबल ऑटोफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

इंटर स्कूल ड्रामा प्रतियोगिता में अलहमद हाई स्कूल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर तृतीय पुरस्कार पर जमाया कब्जा

भिंडी (उत्तरशक्ति)। विद्यार्थियों की छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और सृजनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा अंतर-विद्यालयीन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में सफ़ीना फाउंडेशन और यूनिट थिएटर के संयुक्त तत्वावधान में हर्षीज मैरिज ग्राउंड हॉल में इंटर स्कूल ड्रामा प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में शहर के

विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अल-हमद हाई स्कूल (उ. माध्यम) के कक्षा पाँचवीं से आठवीं तक के 20 विद्यार्थियों के समूह ने भी पूरे जोश और उमंग के साथ सहभागिता की। विद्यार्थियों ने प्रसिद्ध नाटककार सादिक अंसारी द्वारा लिखित तथा नूर आलम अंसारी द्वारा निर्देशित नाटक हूखिजा के फूलहू का प्रभावशाली मंचन प्रस्तुत किया। सशक्त संवाद अदायगी और जीवंत अभिनय ने दर्शकों के साथ-साथ निर्णायक मंडल को भी प्रभावित किया।



निर्णायकों के निर्णयानुसार अल-हमद हाई स्कूल के ड्रामा दल ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता दर्ज की। इसके साथ ही कक्षा सातवीं के छात्र अंसारी अरमश अलतमश को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा कक्षा आठवीं के छात्र शेख नासिर

मोहम्मद लारेब को सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के सम्मान से नवाजा गया। इस शानदार उपलब्धि पर विद्यालय प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों, हेडमिस्ट्रेस, सभी विभागों के प्रभारी शिक्षकों तथा समस्त स्टाफ की ओर से विजेता विद्यार्थियों और मार्गदर्शक शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी गई। साथ ही भविष्य में भी इसी उत्साह और परिश्रम के साथ शैक्षणिक एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की शुभकामनाएँ व्यक्त की गईं।

नवाचार से उद्यमी बने विद्यार्थी: मुकुल वेदी

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के विज्ञान संकाय के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री विभाग द्वारा एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद से पधारे विशेषज्ञ वक्ता मुकुल वेदी ने छात्र-छात्राओं को उद्यमिता एवं नवाचार के विविध आयामों से अवगत कराया।

श्री वेदी ने विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आइडिया से बिजनेस प्लान तक की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। उन्होंने कृषि, पर्यावरण, मेडिकल डिवाइस, फूड सेक्टर,

टिश्यू कल्चर, डायग्नोस्टिक किट, स्टार्टअप संस्कृति तथा नवाचार की आवश्यकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों



पर प्रकाश डाला। साथ ही उद्योगाध्यक्ष सहयोग में ईडीआईआई की भूमिका को

रेखांकित करते हुए विद्यार्थियों को पारंपरिक रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार एवं अनुसंधान आधारित



स्टार्टअप की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शोध, कोशल विकास, इंटरनेट और

नेटवर्किंग के महत्व को बताते हुए कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवा उद्यमी वित्तीय सहायता प्राप्त कर अपने विचारों को व्यवसाय में परिवर्तित कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया सहित विभिन्न करिब संबंधी प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञ वक्ता ने विस्तार से समाधान किया। कार्यक्रम के आयोजन सचिव एवं बायोकेमिस्ट्री विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष कुमार गुप्ता ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए अतिथि वक्ता का स्वागत किया और कहा कि ऐसे व्याख्यान विद्यार्थियों को नई दिशा

एवं दृष्टि प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के संयोजक विज्ञान संकायाध्यक्ष प्रो. राजेश शर्मा ने स्मृति चिह्न भेंट कर मुकुल वेदी का आभार व्यक्त किया। तथा धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस व्याख्यान से विद्यार्थियों को उद्यमिता की समझ विकसित करने में विशेष सहायता मिलेगी। कार्यक्रम का संचालन डॉ. संजीव कुमार मौर्य ने किया एवं अतिथि का जीवन परिचय फूड साइंस टेक्नोलॉजी की छात्रा स्नेहा मौर्य ने प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर एम पी तिवारी, डॉ. ऋषि श्रीवास्तव, डॉ. प्रतिमा, डॉ. श्वेता, डॉ. सिपाही लाल पटेल समेत शोधार्थी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

विधायक के नव विवाहित पुत्र-पुत्र वधू को पीएम ने दी बधाई

आशीर्वाद समारोह में सीएम योगी, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समेत जानी-मानी हस्तियां भी पहुंचीं

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले बदलापुर भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्र के बेटे हर्षित और बहू श्रेया को बधाई दी है। प्रधानमंत्री के आधिकारिक कार्यालय से जारी पत्र को विधायक ने सोशल मीडिया पर शुक्रवार को शेयर किया है। पीएमओ के पत्र के मुताबिक पीएम ने निर्मंत्रण पत्र भेजने पर प्रसन्नता व्यक्त की है और धन्यवाद दिया है। उन्होंने नव विवाहित वधू-वधु को जीवन के नव शुभारंभ की हार्दिक बधाई दी है। साथ ही उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। कहा कि विश्वास और मित्रता की डोर से दोनों सदैव बंधे रहे और रिश्ते में स्नेह बना रहे। उन्होंने बेहतर तालमेल से जीवन आगे बढ़ने और

समय के साथ संबंध और अधिक गहरा तथा मजबूत होने की कामना की है। इसके लिए नव दंपति को दीर्घ, सुखद एवं सौभाग्यपूर्ण जीवन के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया है। विधायक के बड़े सुपुत्र हर्षित के

विवाहोपरान्त जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में आयोजित आशीर्वाद समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उपमुख्यमंत्री द्वय केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, पूर्व गृहमंत्री कृपा शंकर सिंह, शाहजी विधायक रमेश सिंह सहित अन्य लोग भी आशीर्वाद देने पहुंचे थे। इसके लिए विधायक और उनकी पत्नी संजू मिश्रा ने सहाय्य धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है।



विद्युत स्पशार्घात से संविदा लाइनमैन की मौत

सुशील कुमार तिवारी सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। जनपद में इन दोनों विद्युत दुर्घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से आज दिन संविदा कर्मियों की मौत हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन ताजा मामला घोरावल क्षेत्र के सब स्टेशन का है। जहां पर तैनात एक संविदा कर्मी गुरुवार की रात लगभग 6:00 बजे एक ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर रहा था और अचानक विद्युत आपूर्ति चालू हो गई। जिससे वह बहुत बुरी तरह से झुलस गया साथियों के द्वारा उसको तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया जहां पर उपचार के दौरान रात्रि लगभग 1:00 बजे उसकी मौत हो गई।

घोरावल सब स्टेशन पर तैनात संविदा लाइनमैन संतोष पुत्र चित्तामणि निवासी घोरावल जो विद्युत विभाग में संविदा लाइनमैन के पद पर कार्यरत था। गुरुवार की रात लगभग 6:00 बजे वह एक ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर कार्य कर रहा था। तभी अचानक विद्युत

आपूर्ति चालू हो गई और वह बुरी तरह से झुलस गया। मौके पर उपस्थित कर्मचारी और स्थानीय लोगों के सहयोग से उसे जिला



अस्पताल लाया गया जहां इलाज के दौरान रात्रि लगभग 1:00 बजे उसकी मौत हो गई। सवाल यह उठता है कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से संविदा कर्मियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, आखिर यह कब तक चलता रहेगा।

संविदा कर्मी अल्प वेतन में किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। क्या यह अधिकारियों को नहीं मालूम उसके

बाद भी लगातार उनका शोषण होता रहता है। कभी अधिकारियों के द्वारा तो कभी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा काम का बोझ और मानसिक दबाव के चलते आए दिन संविदा कर्मी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है। सवाल यह उठता है कि जिस परिवार के उनका कमाओ पुत चला जाता है उसे परिवार की रोजी-रोटी किसके भरसे चलेगी विभाग में भ्रष्टाचार इस तरह हावी है। कि कभी-कभी इन कर्मचारियों को विभाग अपना कर्मचारी मानने से इनकार कर देता है जिससे उनका परिवार सड़को पर आ जाता है और भुखमरी के कगार पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ यही अधिकारी उन घटनाओं पर पर्दा डाल करके चैन की नौद अपने घरों और ऐसी रूप में बैठकर अपने रहते हैं। इनक की कुंभकर्णी नौद कब टूटेगी।

खेत से लापता हुई युवती, परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

केराकत, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। केराकत कोतवाली क्षेत्र के मुर्की गांव से एक युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जौनपुर जिले के केराकत थाना क्षेत्र के मुर्की गांव निवासी प्रेम पुत्र विश्वनाथ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी 21 वर्षीय पुत्री सीमा 24 फरवरी 2026 को शाम करीब 4 बजे गन्ने के खेत में गई थी। वहां से उसने घर फोन कर बताया कि वह घर आ रही है। परंतु शाम करीब 6 बजे जब वह घर पहुंचे तो उनकी पुत्री घर पर नहीं थी। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका। परिजनों को आशंका है कि किसी ने बहला-फुसलाकर युवती को अपने साथ ले गया है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच उपनिरीक्षक राकेश कुमार सोनकर को सौंपी गई है। पुलिस युवती की तलाश में जुटी हुई है।

भैंस चोरी की वारदात से पशु पालकों में दहशत

सुजानगंज, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। क्षेत्र के शिवरिहा ग्राम में चूहस्तितार की बीती रात चोरों ने किसान की भैंस चोरी कर लिए। जानकारी अनुसार शिवरिहा निवासी पीड़ित दयाराम यादव ने सुजानगंज थाना पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले हमारे यहां पशु तस्करों के आरोपी रामचंद्र उपाध्याय निवासी पटुआ व पशु व्यापारी शेरु बाल्हामक हमारी भैंस व पीडियां बेचने के लिए कह रहे थे जिसको मैंने मना कर दिया। जिसके बाद चूहस्तितार को बीती रात मेरी भैंस व प प पडिया चोरी हो गईं, पीड़ित ने उक्त दोनों व्यक्ति रामचंद्र उपाध्याय व शेरु के उपर ही आरोप लगाए हैं कि इन्होंने दोनों की मिली भगत से हमारी भैंस व पडिया चोरी हुई है। इस मामले को लेकर पीड़ित द्वारा एक सीसीटीवी कैमरे का वीडियो भी दिखाया जा रहा है जिसमें छद्म जाहा है कि एक पिकअप वाहन पर रात में कोई व्यक्ति भैंस लेकर जा रहा है।

साई बाबा का जीवन मानवता को रहा समर्पित: रमेश सिंह

धूमधाम से मनाया गया साई बाबा मंदिर का 26 वाँ वार्षिकोत्सव

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। सुइथाकला विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत बसौली स्थित साई प्रसाद ग्रहण किये। शाम को विधायक रमेश सिंह ने मंदिर में पहुंचकर साई बाबा के चरणों में मत्था टेका, दर्शन एवं पूजा अर्चना की। विधायक ने कहा कि साई बाबा का जीवन मानवता को समर्पित रहा। उन्होंने मानव को दया, करुणा, सत्य और अहिंसा की राह पर चलना सिखाया। कहा कि उनका जीवन संपूर्ण मानव जाति के लिए अनुकरणीय है। मुख्य आयोजक हनुमान शरण सिंह ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर क्षेत्रवासियों के मन में अपार उत्साह है। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्रशासन, स्वयंसेवकों

का बाबा मंदिर का 26 वाँ वार्षिकोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया। मंदिर परिसर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में देर शाम तक भक्तों का सैलाब उमड़ा रहा। मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने

एवं क्षेत्रवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पीएसी सहित सरपतहा, खुटहन और करौदी कला पुलिस फोर्स तैनात रही। वार्षिकोत्सव में शामिल होने के लिए जौनपुर जनपद के अलावा बनारस, मुगलसराय, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर

नगर, आजमगढ़ सहित अन्य समिति जनपदों सबसे श्रद्धालु पहुंचे।

मां का दिव्य दर्शन करके अभिभूत हूं: विधायक

देवी धाम बसौली में विधायक रमेश सिंह ने टेका मत्था

विधायक रमेश सिंह ने बसौली के देवी धाम में गुरुवार की देर शाम शीतला माता मंदिर में मत्था

टेक कर आशीर्वाद लिया। मंदिर के मुख्य पुजारी पीड़ित रमेश तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना कराया। विधायक ने कहा कि मां का दिव्य और अलौकिक दर्शन करके अभिभूत हूं। मां आदिशक्ति एवं जगत जननी हैं जिनकी लीला अपरंपर है। मां का आध्यात्मिक तेज कण-कण में विराजमान है। विधायक ने बताया कि यह एक अद्भुत एवं जीवंत शक्तिपीठ है जहां आकर भक्तों की मन्त्रों पूरी होती हैं। मुख्य पुजारी ने कहा कि यह मंदिर 14 कोस की परिधि के लोगों के लिए आस्था भक्ति श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। यहां से भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। जो भी निष्काम भाव से माता रानी के दरबार में आता है मां उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। नगर, आजमगढ़ सहित अन्य समिति जनपदों

सबसे श्रद्धालु पहुंचे।

गोपालापुर में लगा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, विशेषज्ञ डॉक्टरों ने की जांच

पेटल हॉस्पिटल व आसरा फाउंडेशन की पहल, सैकड़ों ग्रामीणों ने उठाया लाभ

धमापुर, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। धमापुर ब्लॉक की गोपालापुर ग्रामसभा में रविवार को पेटल हॉस्पिटल द्वारा आसरा फाउंडेशन के सहयोग से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करना रहा। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच व चिकित्सकीय परामर्श का लाभ उठाया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने ओपीडी के माध्यम से मरीजों की जांच की और आवश्यक सलाह दी। इस दौरान डॉ. डी. के. सिंह (ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ), डॉ. अभिषेक मिश्रा (MBBS, MD मेडिसिन) तथा डॉ. कनीज फातिमा (MBBS, MS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ) ने मरीजों की विस्तार से जांच की। जरूरतमंद

मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए नियमित जांच और संतुलित जीवशाैली अपनाने की सलाह दी गई। पेटल हॉस्पिटल के संस्थापक जमान साकलेन ने बताया कि अस्पताल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी ऐसे निशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन लगातार किया जाता रहेगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को समय पर जांच और उचित उपचार मिल सके। स्थानीय ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि गांव स्तर पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता से उन्हें काफी राहत मिली है। लोगों का कहना था कि इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर समाज के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं और इससे गरीब व जरूरतमंद मरीजों को सौधा लाभ मिलता है।

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) भौतिक विज्ञान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की पूर्व संख्या कि विभिन्न शैक्षणिक एवं रचनात्मक प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत पोस्टर, रंगोली, विजज एवं निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार की भावना तथा विज्ञान के

पोस्टर, रंगोली, विजज, निबंध प्रतियोगिताओं में छात्रों की उत्साहपूर्ण सहभागिता

प्रति गहरी रुचि विकसित करना था। पोस्टर एवं रंगोली प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास जैसे समासांमयिक विषयों को सृजनात्मक और आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया। विजज प्रतियोगिता में छात्रों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी ज्ञान क्षमता और त्वरित निर्णय कौशल का परिचय दिया। वहीं निबंध प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने विज्ञान की भूमिका, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा समाज पर उसके प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किए। आदिछात्रा छात्र कल्याण एवं

रचनात्मकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जैसे अवसर विद्यार्थियों को विज्ञान के महत्व को समझने और नवाचार के लिए प्रेरित करने का सशक्त माध्यम हैं। इस अवसर पर आयोजन सचिव

विज्ञान दिवस की पूर्व संख्या पर विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन



कार्यक्रम संयोजक प्रो. प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, तार्किक क्षमता एवं रचनात्मकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जैसे अवसर विद्यार्थियों को विज्ञान के महत्व को समझने और नवाचार के लिए प्रेरित करने का सशक्त माध्यम हैं। इस अवसर पर आयोजन सचिव

आज दुनिया को और अधिक हथियारों की नहीं, न्याय की जरूरत

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे पर मोहम्मद अरशद खान का वक्तव्य— न्याय, मानवता और वैश्विक जिम्मेदारी की पुकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा के जौनपुर सदस्य पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे पर एक मजबूत और गहन मानवीय दृष्टिकोण से अपना वक्तव्य जारी किया है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया गज में अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी की साक्षी बन रही है। आज जब गजा में नागरिकों की विनाशकारी मृत्यु से वैश्विक अंतरात्मा झकझोर दी गई है, जब मासूम बच्चों की कनिजी देह मलबे के नीचे से निकाली जा रही है, जब हजारों माताएं अपने बच्चों के अपूरणीय नुकसान पर शोकमन हैं, और जब लाखों नागरिक पीड़ा, चोट, विस्थापन

और निराशा में जीवन जीने को मजबूर हैं— ऐसे समय में प्रधानमंत्री का यह दौरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने गंभीर नैतिक, मानवीय और नैतिक प्रश्न खड़े करता है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अब तक 72,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ये केवल आँकड़े नहीं हैं— ये टूटे हुए परिवारों, बर्बाद भविष्य और मानवता की अंतरात्मा पर लगे गहरे घाव का प्रतीक हैं। यह त्रासदी वैश्विक न्याय, मानव गरिमा और सभ्य समाज के मूल सिद्धांतों की नींव को हिला रही है। महात्मा गांधी और बौद्ध की धरती भारत— जो शांति, अहिंसा, न्याय और नैतिक साहस का शाश्वत प्रतीक है— ऐतिहासिक रूप से हमेशा उदारता, वंचितों और अन्याय के शिकारियों के साथ खड़ा रहा है। भारत की वैश्विक पहचान शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, मानवाधिकारों और नैतिक नेतृत्व के सिद्धांतों पर आधारित रही है।



मानव इतिहास के इस निर्णायक मोड़ पर केवल कूटनीतिक औपचारिकताओं तक सीमित रहना नहीं है। एक उच्च नैतिक दायित्व रोजूद है— मानवता के पक्ष में हड़ता से खड़े होने का दायित्व। इजराइल की धरती से ही भारत को एक स्पष्ट, सिद्धांतपरक और साहसिक आवाज उठानी चाहिए, जिसमें

गजा में मासूम नागरिकों, विशेषकर बच्चों, महिलाओं और निर्दोष लोगों की हत्या को तत्काल रोकने की मांग की जाए। गजा में नागरिक जीवन का व्यवस्थित विनाश, बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करना और व्यापक मानवीय तबाही किसी भी परिस्थिति में न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (कठउ) द्वारा इजराइल के प्रधानमंत्री बेनजामिन नेतान्याहू के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना इस मानवीय संकट की गंभीरता की वैश्विक स्वीकृति को दर्शाता है और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जवाबदेही सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। आज दुनिया को और अधिक हथियारों की नहीं— न्याय की आवश्यकता है। दुनिया को मौन की नहीं— नैतिक साहस की आवश्यकता है। दुनिया को राजनीतिक तटस्थता की नहीं— बल्कि मानवता पर

आधारित सिद्धांतपरक नेतृत्व की आवश्यकता है। न्याय, मानवता और शांति में विश्वास रखने वाले करोड़ों लोगों की ओर से, मोहम्मद अरशद खान भारत सरकार और प्रधानमंत्री से आह्वान करते हैं कि वे 140 करोड़ भारतीयों की नैतिक चेतना का सम्मान करें और गजा में पीड़ित निर्दोष नागरिकों के समर्थन में स्पष्ट, सशक्त और अडिग आवाज उठाएं। भारत को रक्तपात को तत्काल रोकने तथा न्याय, जवाबदेही और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर रचनात्मक और निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। इतिहास केवल नेताओं के कार्यों को ही नहीं— बल्कि अन्याय के क्षणों में उनकी चुप्पी को भी याद रखता है। अब बोलने का समय है। अब कार्य करने का समय है। मानवता की विजय हो। न्याय की विजय हो।

केराकत में खड़ी बाइक चोरी, पीड़ित ने दर्ज कराई एफआईआर

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। केराकत क्षेत्र में खड़ी मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार जौनपुर जिले के केराकत थाना क्षेत्र के पसारा गांव निवासी लक्ष्मण सरोज ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 25 फरवरी 2026 को वह अपनी मोटरसाइकिल (यूपीपी 7936) से आजमगढ़ के लालागंज से अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में लालजी इंटर कॉलेज तिराहा के पास उन्होंने गाड़ी खड़ी कर थोड़ी देर के लिए चले गए। जब वह वापस लौटे तो उनकी मोटरसाइकिल मौके से गायब थी। काफी खोजबीन के बाद भी बाइक का कोई पता नहीं चल सका। घटना शाम करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर केराकत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक सुरेश कुमार सिंह को सौंपी गई है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में जांच कर रही है तथा चोरों की तलाश में जुटी हुई है।

